was focussed mainly on a national public awareness campaign to make the role and rights of women recognised and understood by all sections of people. Educating the people and changing attitudes is a complex and long term process and it is continuing.

2. However, a few projects did get started in International Women's Year as shown below:—

(i) Functional Literacy for Women in the age group of 15—45 years.

In the experimental scheme of the Integrated Child Development Services, it was decided to attempt to implement a scheme of functional literacy for women. The Scheme imparts training in health and nutrition, education, child care and programmes of supplementary income like kitchen gardening, poultry keeping, animal husbandry etc. and is now being implemented in 2628 centres in 31 project areas. 43168 women are reported to have been covered by the Scheme in 1976-77. An amount of Rs. 57.50 lakhs is provided for the Scheme in 1977-78, the amount spent in 1976-77 being Rs. 22.25 lakhs.

(ii) The Scheme for assisting voluntary organisations in the construction of Working Women's Hostels was liberalised in January 1975. The quantum of assistance for construction, given by the Central Government was raised from 60 per cent to 75 per cent from January 1975, and this pattern is continuing. The expenditure on the Working Women's Hostal Scheme rose from Rs. 52.40 lakhs in 1974-75 to Rs. 81.80 lakhs in 1975-76 and to Rs. 90.04 lakhs in 1976-77. An amount of Rs. 161.50 lakhs is provided for 1977-78.

(iii) A scheme of assistance to voluntary organisations for provision of creches for children of working and ailing mothers was finalised during the International Women's Year. In 1976-77, a sum of Rs. 25 lakhs was sanctioned as assistance covering 19050 beneficiaries (Children).

Ban on prostitution

3046. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to ban prostitution in the country; and

(b) if so, what are the plans for rehabilitating the prostitutes?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) There is no such proposal.
(b) Does not arise.

World Bank assistance for the Upper Krishna Projects

3047. SHRI RAJSHEKHAR KOLUR: SHRI TULSIDAS DASAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there has been any progress in negotiation in respect of World Bank assistance for the Upper Krishna Project in Karnataka between Government of India and the World Bank;

(b) whether the Government of India is giving substantial assistance for accelerating the Upper Krishna Project work; and

(c) if so, when and how much financial assistance was given?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) An Appraisal Mission of the World Bank is expected to visit the Upper Krishna Project in September, 1977.

(b) and (c). An advance plan assistance of Rupees two crores was provided to the Government of Karnataka during 1976-77 with a view to accelerate the tempo of works on the project.

"सुन्दरकली" नामक कम आयु के हाथी का रोगग्रस्त होना

3049. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालुम है कि 'सुन्दरकली' नामक कम आयु का एक हाथी अगली टांग की हड्डी टूट जाने से रोगग्रस्त है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसकी जिन्दगी बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या हिसार से आये डाक्टर उसके जिन्दा रहने की आशा रखते हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है ; और

(घ) क्या सरकार ने डाक्टर द्वारा अपेक्षित क्रेन भिजवाने के लिये रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) "सुन्दरकली" नामक हथनी एक प्राइवेट फर्म की थी । इस फर्म ने हथनी की जांच करने के लिये दिनांक 25-6-77 को दिल्ली चिडियाघर के निदेशक से अनुरोध किया था । चिड़ियाघर के अधिकारियों ने (जिनमें चिड़ियाघर के अवैतनिक पशु-चिकित्सा सलाहकार भी शामिल थे) हथनी की तत्काल जांच करके फर्म को सुझाव दिया कि ऐसे मामले में, जबकि एक टांग में विवत अस्थिभंग (कमपाउंड फ्रेकचर) हो गया हो और जिसका उस अवस्था में उपचार नहीं हो सकता हो, मानवीय ढंग से मार देना ही एक मात्र उपाय है । अब इस हथनी की मृत्यु हो चुकी है ।

(ग) सरकार के पास हिसार के डाक्टरों के मत के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(घ) जी हां ।

दिल्ली की सी० एस० पी० कालोनियों में हाऊस टैक्स लगाना

3050. **श्री राम निरेश कुशवाहा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारों काम्युनिटी सर्विस पर्सनल कालोनियों को दिल्ली नगर निगम को दिया गया है और निगम ने इन कालोनियों के निवासियों पर हाऊस टैक्स लगा दिया है ;

(ख) क्या इन कालोनियों के निवासी अब तक इन मकानों के मालिक नहीं हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण को मासिक किस्तों पर भुगतान कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा कालोनियों को अपने अधीन लेने के बारे में सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है । यह सूचित किया गया है कि नगर निगम उनकी सम्पत्ति पर गृहकर लगा रहा है ।